

## वार्षिक रिपोर्ट 1998-99 Annual Report



*Union Bank  
Reflecting the dawn of a new millennium.*

यूनिऑन बैंक ऑफ इंडिया  
अच्छे लोग अच्छा बैंक



**UNION BANK OF INDIA**  
*Good people to bank with*

# महत्वपूर्ण उपलब्धियां

## Highlights

(रु. करोड़ में)  
(Rs. in crore)  
मार्च  
March 1999

पूंजी और आरक्षितियां Capital & Reserves	1,683
शाखाएं (संख्या) Branches (Nos.)	2,119
विशेषीकृत शाखाएं Specialised Branches	139
कुल जमा राशियां Total Deposits	28,136
सकल बैंक ऋण Gross Bank Credit	11,787
बाजारोन्मुख निवेश (%) Investments Marked To Market (%)	86.02
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अग्रिम Priority Sector Advances	4,684
निर्यात ऋण Export Credit	1,482
स्टाफ (संख्या) Staff (Nos.)	30,834
उत्पादकता (रु. लाख) Productivity (Rs. in Lacs)	113.12
शुद्ध लाभ Net Profit	160.22
पूंजी पर्याप्तता (%) Capital Adequacy (%)	10.09
स्तर - I पूंजी Tier - I Capital (%)	7.87

# विषय सूची CONTENTS

निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट Report of the Board of Directors	8
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट Auditor's Report	46
तुलन-पत्र Balance Sheet	48
लाभ व हानि लेखा Profit and Loss Account	49
अनुसूचियां Schedules	50



**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया**  
**UNION BANK OF INDIA**

प्रधान कार्यालय : 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021

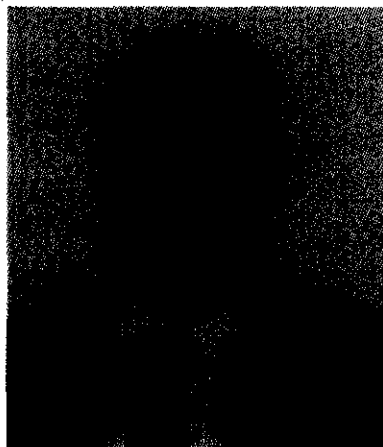
HEAD OFFICE : 239, VIDHAN BHAVAN MARG, NARIMAN POINT, MUMBAI-400 021

फोन/PHONE : 2024647, 2026049 फैक्स/FAX: 2025238

वेबसाइट/WEBSITE: <http://www.unionbankofindia.com>

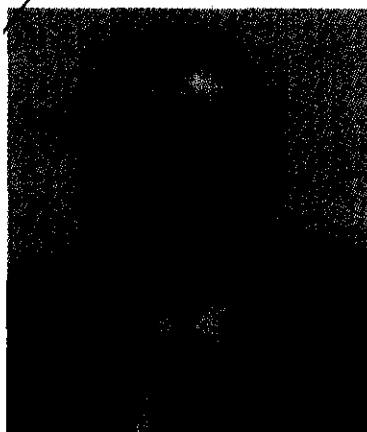


# निदेशक बोर्ड BOARD OF DIRECTORS



ए. टी. पन्नीर सेल्वम  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक  
A.T. PANNIR SELVAM  
Chairman & Managing Director

Report Junction.com



डि.टि. पै  
कार्यपालक निदेशक  
D.T. PAI  
Executive Director

# निदेशक बोर्ड

# BOARD OF DIRECTORS



आलोक कुमार  
ALOK KUMAR



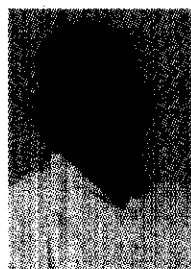
श्रीमती श्यामला गोपीनाथ  
Smt SHYAMALA GOPINATH



एस. के. मित्रल  
S.K. MITTAL



एच. एफ. खोराकीवाला  
H.F. KHORAKIWALA



वी. एच. देसाई  
V.H. DESAI



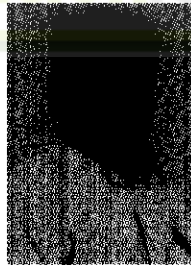
जी. सत्यनारायण  
G. SATYANARAYANA



डॉ. बहुरा एक्का  
DR. BAHURA EKKAR



शफायत हुसैन  
SHAFAYET HUSAIN



एम. पी. कृष्णप्पा  
M.P. KRISHNAPPA



आर. के. अग्रवाल  
R.K. AGARWAL



पी. के. सरकार  
P.K. SARKAR

## लेखापरीक्षक

बी.एम. चत्रथ एण्ड कं.  
एल.बी. झा एण्ड कं.  
एल.एस. नलवाया एण्ड कं.  
एस.एन. नंदा एण्ड कं.  
वी.पी. आदित्य एण्ड कं.  
वेद एण्ड कं.

## AUDITORS

B.M. Chatrath & Co.  
L. B. Jha & Co.  
L.S. Nalwaya & Co.  
S.N. Nanda & Co.  
V.P. Aditya & Co.  
Ved & co.

# कार्यपालक / EXECUTIVES

## महाप्रबंधक / General Managers

जी. आर. आनंद	G.R. Ananda
माइकल बास्टियन	Michael Bastian
एस. पी. राय	S.P. Roy
टी. एस. नारायणसामी	T.S. Narayanasami
वी. श्रीधर	V. Sridar
के. वी. एस. श्यामसुन्दर	K.V.S. Shyamsunder
एस. पी. एस. वालिया	S.P.S. Walia
के. एस. राव	K.S. Rao
एम. एस. मोहन	M.S. Mohan
सुश्री एच. ए. दारुवाला	Ms. H.A. Daruwalla
के. एम. एस. बाबूगुप्ता	K.M.S. Babugupta
एस. एन. अय्यर	S.N. Iyer

## उप महाप्रबंधक / Deputy General Managers

एस. एच. एच. जैदी	S.H.H. Zaidi
आर. वेंकटरमणी	R. Venkatramani
आर. नारायणस्वामी	R. Narayanaswamy
ए. एस. भट्टाचार्य	A.S. Bhattacharya
के. एस. राघवन	K.S. Raghavan
वी. एस. आर. मूर्ति	V. S. R. Murthy
पी. डी. मडिमन	P.D. Madiman
डी. एस. प्रकाश राव	D.S. Prakasa Rao
आर. बी. मिस्त्री	R.B. Mistry
एम. बी. तवाडिया	M.B. Tavadia
के. पी. लाझर	K.P. Lazar
वी. बी. नायक	V.B. Naik
बी. एल. जवेरी	B.L. Javeri
के. एल. गोपालकृष्ण	K.L. Gopalkrishna
आर. ए. अग्रवाल	R.A. Agarwal
पी. के. जैन	P.K. Jain
ए. ए. ताज	A.A. Taj
अली सादिक	Ali Sadiq
एस. सी. चौबे	S.C. Chaubey
ए. एच. जोशी	A.H. Joshi
पी. एन. सुब्रमण्यम	P.N. Subramanyam
एम. गनूरकर	M. Ganoorkar
आर. विश्वनाथन	R. Vishwanathan



# बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट

## 1998-99

### ◀ समष्टि अर्थव्यवस्था ▶

यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की गयी है कि वर्ष 1998-99 के दौरान काफी अशांत और विपरीत अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक वातावरण की पृष्ठभूमि में भारत का आर्थिक विकास काफी उल्लेखनीय रहा. वर्ष के दौरान कई पूर्व-एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी में संकुचन आया, जापान में आर्थिक मंदी, रुस में आर्थिक कमी, पूंजी और फॉरेक्स बाजार में असाधारण परिवर्तनशीलता के कारण पूंजी प्रवाह में कमी तथा ब्राजील में मुद्रा में अत्यधिक अवमूल्यन आया. पूर्व एशियाई 'परिवर्तनों' से विश्व अर्थ व्यवस्था तथा कीमतों में मंदी का दौर आरंभ हुआ. वर्ष के दौरान यद्यपि भारत इन स्थितियों से पूर्णतः अछूता न रहा, तथापि अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रभावित भी नहीं हुआ.

भारत द्वारा दर्ज 5.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कई अर्थव्यवस्थाओं में बेहतर रही. इस वृद्धि में कृषि उपज में 5.3 प्रतिशत की तथा सेवा क्षेत्र आय में 7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी. तथापि औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्ष की 6.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 3.8 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर्ज की गयी. स्टील, कपड़ा, सीमेंट, वाहन उद्योग तथा उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन लगातार दूसरे वर्ष भी आर्थिक मंदी से प्रभावित रहा. औद्योगिक मंदी अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आवक तथा निर्यात मांग में कमी के कारण अधिक गंभीर हुई.

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 3.6 बिलियन

अमेरिकी डालर से कम होकर 2.5 बिलि. अमेरिकी डालर रहा. जीडीआर/इसीबी के जरिये विदेशी मुद्रा आवक पिछले वर्ष के 291 मिलि. अमेरिकी डालर से कम होकर 70 मिलि. अमेरिकी डालर रह गयी.

वर्ष के दौरान भारत से दक्षिण और पूर्व एशिया, यूरोप तथा ओसिनिया देशों के निर्यात में कमी आयी. तथापि अमेरिका और अफ्रीका को निर्यात में लाभप्रद वृद्धि हुई. परिणामस्वरूप, निर्यात 35.1 बिलि. अमेरिकी डालर से घटकर 33.7 बिलि. अमेरिकी डालर रह गया. भारत का आयात 41.5 बिलि. अमेरिकी डालर से थोड़ा बढ़कर 41.8 बिलि. अमेरिकी डालर हुआ. मुख्यतः पेट्रोलियम कूड के आयात की अल्प लागत के कारण आयात वृद्धि नियंत्रित रही. समग्र रूप से चालू खाते में घाटा, पिछले वर्ष के 1.3 प्रतिशत की तुलना में जीडीपी का 1.0 प्रतिशत रहा.

भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिसर्जन्ट इंडिया बॉन्ड्स की सहायता से 25.9 बिलि. अमेरिकी डालर से बढ़कर 29.5 बिलि. अमेरिकी डालर हो गया. अर्थव्यवस्था की आवश्यकतानुसार, वर्तमान आयात और अल्पावधि बाह्य देयताओं तथा पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह को देखते हुए विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति संतोषजनक पायी गयी.

भारतीय अर्थव्यवस्था का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू मांग में बढ़ोतरी पर निर्भर प्रतीत होता है. विश्व मांग धीरे-धीरे बढ़ रही है. कृषि उत्पादन में पिछले वर्ष की बढ़ोतरी, वर्ष 1999-2000 में प्रभावी मांग तथा औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए वर्धक बनने की आशा है.

अगले सहस्राब्दि की शुरुआत में, भारत को बाह्य स्पर्धात्मक वातावरण से पृथक करनेवाले संरक्षी बाजार के परंपरागत कवच को काफी हद तक त्यागना होगा. चूंकि भारत, विश्व अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ रहा है, अतः उस पर समष्टि अर्थव्यवस्था में होनेवाले बाह्य उतार-चढ़ाव तथा वित्तीय परिवर्तनों का भारी प्रभाव होगा. पहले ही भारतीय स्टॉक, फॉरेक्स तथा मुद्रा बाजार ने अन्तर्राष्ट्रीय सहभाग विकसित किया है.

### ◀ मुद्रा नीति संबंधी गतिविधियां ▶

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) ने वित्तीय वर्ष के दौरान उनके मुद्रा नीति वक्तव्यों में मध्यम/दीर्घावधि/संरचनात्मक मामलों पर ध्यान केन्द्रित किया है. सीआरआर, एसएलआर, बैंक दर, रेपो दर तथा पुनर्वित्त में परिवर्तन जैसे अल्पावधि नीति उपाय अब इसके अंग नहीं हैं. इसमें आवश्यकतानुसार वर्ष के दौरान कभी भी परिवर्तन किये गये.

पूर्व एशियाई संकट के परिणामों से भारिबैं ने महसूस किया कि सार्वभौमिक अर्थव्यवस्थाओं में बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता अत्यधिक महत्वपूर्ण है. अतः समयबद्ध कार्यक्रमों में विवेकपूर्ण मानदंडों में अधिक तर्कसंगतता, उच्चतर पूंजी पर्याप्तता कवर करना, साथ ही मानक आस्तियों के पेटे प्रावधान, सरकार/द्वारा गारंटीकृत ऋण तथा तुलन-पत्र में शामिल न की गयी जोखिमों की ओर ध्यान दिया गया. ब्याज दरों का विनियंत्रण तथा बैंकों को ऊंची

# THE BOARD'S ANNUAL REPORT :

## 1998-99

### ◀ The Macro-Economy ▶

It has been widely recognised that India's economic development during 1998-99 is quite noteworthy when seen against the background of extraordinarily turbulent and adverse international economic environment. The year was marked by a contraction in the GDP of several East Asian economies, recession in Japan, a financial crunch in Russia, exceptional volatility in the capital and FOREX markets, receding capital flows and a steep devaluation in Brazil. The East-Asian 'meltdown' triggered off a slowdown in the world economy and eased prices. India, though not completely immune to these developments, emerged relatively unscathed during the year.

India logged a real GDP growth rate of 5.8 per cent outperforming a large number of economies. This growth was spurred by an incremental 5.3 per cent in agricultural output alongside a rise of 7 per cent in service sector income. Industrial production, however, registered a slower growth of 3.8 per cent, compared to 6.6 per cent in the previous year. Industries like steel, textiles, cement, vehicles and consumer goods continued to remain in a recessionary grip for the second successive year. The industrial slackening was aggravated by the receding international capital inflows and demand for exports.

Foreign Direct Investments into India registered a fall from US \$3.6 bn. to US \$2.5 bn. GDR/ECB floatations trickled down to US \$70 mn. from US \$291 mn. in the previous year.

Indian exports to South and East Asia, Europe and Oceania countries receded during the year. Exports to US and Africa, however, registered healthy growth. Consequently, exports slipped marginally from US \$35.1 bn. to US \$33.7 bn. Imports into India increased at a relatively slower rate from US \$41.5 bn. to US \$41.8 bn., principally owing to the lower cost of petroleum crude. Overall, the current account deficit constituted 1.0 per cent of GDP compared to 1.3 per cent a year earlier.

India's FOREX reserves, bolstered by Resurgent India Bonds, improved from US \$25.9 bn. to US \$29.5 bn. In relation to the economy's needs, judged by the prevailing imports and the short-term external liabilities and portfolio flows, the foreign currency reserves were at a comfortable level.

The prospects for the Indian economy appear to hinge on a revival of international as well as domestic demand. World demand appears to be inching up. Last year's boost to agricultural output is expected to act as a booster for effective demand and an industrial revival in 1999-2000.

On the threshold of the next millennium, India has to a large extent shed its traditional cocoon of a protective market insulated from

external competitive environment. As India integrates with the mainstream world economy, it will increasingly be affected by external fluctuations in macro-economic and financial variables. Already, Indian Stock, FOREX and Money Markets have developed international linkages.

### ➤ Monetary Policy Developments ◀

Reserve Bank of India (RBI) focussed on medium/long term / structural issues in their policy statements during the financial year. Short term policy measures like changes in CRR, SLR, Bank Rate, Repo Rate and Refinance were no longer timed with these statements. These issues were addressed whenever warranted during the course of the year.

In the aftermath of the East Asia crisis RBI recognised that financial strength of the banking sector was of critical importance to globalising economies. Therefore, greater stringency in prudential norms, covering higher capital adequacy, as also provisioning against standard assets, government/government guaranteed loans and off-balance sheet exposures were advocated under a time-bound programme.

With the deregulation of interest rates and discretion given to banks to mobilise high value deposits at premium rates, the operational risks





दरों पर उच्च मूल्य की जमाराशियों के संग्रहण हेतु दिये गये विवेकाधिकार से बैंकिंग प्रणाली पर आयी परिचालनात्मक जोखिम काफी हद तक बढ़ गयी है। अतः भारिबैं ने दि. 1 अप्रैल, 1999 से आस्तियों और देयताओं के प्रबंधन की पद्धति को समाविष्ट करना बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया।

वर्ष 1998-99 के दौरान भारिबैं ने फॉरेक्स मार्केट स्थिर करने, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने, सरकार द्वारा उधार लेने की प्रक्रिया का प्रबंध करना, मुद्रास्फीति में कमी सुनिश्चित करना तथा ब्याज दरों में कमी लाने हेतु नीतिगत उपाय किये। उन्होंने इसे खुले बाजार परिचालन, रेपो लेन-देन, सीआरआर में परिवर्तन, सरकारी ऋणों का निजी नियोजन तथा बैंक दर में परिवर्तन के माध्यम से पाने का प्रयास किया। इन अल्पावधि उपायों का लक्ष्य निर्धारित दायरे में मुद्रा आपूर्ति वृद्धि दर का नियंत्रण तथा अनुश्रवण के परंपरागत उपाय के स्थान पर, आपाती आवश्यकताओं के अनुसार बैंकिंग प्रणाली की तरलता का नियंत्रण करना था।

इस नयी नीति का उद्देश्य, “मुद्रा आपूर्ति : विश्लेषण और संकलन” प्रणाली पर गठित कार्यदल की संस्तुति तथा उसके कार्यान्वयन से समर्थित प्रतीत होता है। कार्यदल ने मुद्रा आपूर्ति के साथ-साथ तरलता उपायों पर भी जोर दिया था।

औद्योगिक कार्यकलाप की मंदी पर ध्यान देते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने मुद्रा आपूर्ति (एम3) निर्धारित 15.0-15.5 प्रतिशत की सीमा से आगे बढ़ने के बावजूद इसे रोकने के प्रयास नहीं किये। इसी प्रकार वर्ष के मध्य जब मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि हुई, तब यह जानते हुए कि यह तेजी कुछ वस्तुओं के

अल्पकालिक आपूर्ति अवरोध के कारण है, वे प्रतिबंधात्मक उपायों से बचे रहे।

कुल मिलाकर वर्ष के दौरान सुलभ तरलता, भारिबैं को सीआरआर (मध्यावधि नीति लक्ष्य के अनुसार) को कम करने से रोकती रही। फॉरेक्स मार्केट की अस्थिरता को रोकने के लिए वर्ष के आरंभ में रही सीआरआर की 10 प्रतिशत की दर अगस्त, 98 में 11 प्रतिशत तक बढ़ायी गयी। इसके बाद मार्च, 1999 में ब्याज दरों को कम करने के उद्देश्य से तरलता बढ़ाने के लिए इसे 10.5 प्रतिशत तक कम कर दिया गया।

थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर एक वर्ष पहले के 5.3 प्रतिशत की तुलना में मार्च, 1999 में 5 प्रतिशत रही जिससे मूल्य स्थिति और अधिक सहज हुई।

### ◀ बैंकिंग प्रवृत्ति ▶

वर्ष 1998-99 में ब्याज दरों में सांकेतिक गिरावट आई। बढ़ी तरलता के कारण, प्रमुख बैंकों ने जमाराशि दरों में परिवर्तन से पहले ही ऋणों पर ब्याज दरों में कटौती कर दी। यह शायद लगातार दूसरे वर्ष भी ऋण की मांग में वृद्धि न होने पर उनकी चिंता के कारण था। अधिकांश ऋण दरें पीएलआर से संबद्ध होने के कारण, अधोमुखी समायोजन के परिणामस्वरूप आय में सभी स्तरों पर कमी आई। दूसरी तरफ जमा ब्याज दरों में कमी से केवल नयी/नवीकृत जमा प्रभावित हुई हैं। इस प्रक्रिया के दौरान चूंकि जमाराशियों में वर्ष 1998-99 में बढ़ोत्तरी जारी रही, जिसके फलस्वरूप आय-लागत अंतर और कम हो गया।

बैंकिंग प्रणाली की कुल जमाराशियां पिछले

वर्ष के रु. 6,05,410 करोड़ की तुलना में रु. 7,17,271 करोड़ तक पहुंच गयी। इस साल की वृद्धि पिछले साल के 19.7 प्रतिशत की तुलना में 18.5 प्रतिशत रही।

जमाराशि वृद्धि में यह विशेषता थी कि सावधि जमाराशियों में तीव्र वृद्धि हुई जबकि मांग जमाराशियों में कमी आयी। वर्ष के दौरान कुल जमाराशियों में रु. 1,11,861 करोड़ की कुल वृद्धि में मीयादी जमा घटक का हिस्सा रु. 1,00,894 करोड़ था। परिणामस्वरूप मीयादी जमाराशियों का हिस्सा 83.1 प्रतिशत से बढ़कर 84.2 प्रतिशत हो गया। रिसर्जेंट इंडिया बॉन्ड के कारण हुई वृद्धि पर ध्यान न दें तब भी मीयादी जमा घटक 83.7 प्रतिशत बढ़ गया।

मीयादी जमा में वृद्धि का कारण 15-29 दिनों की अवधि वाली नयी परिपक्वता अवधि की शुरुआत करना भी हो सकता है। अन्य कारण सेवा क्षेत्र की प्रयोज्य आय में वृद्धि हो सकती है।

बैंकिंग प्रणाली के कुल बैंक ऋण में पिछले वर्ष रु. 45,678 करोड़ (16.4%) की तुलना में इस वर्ष केवल रु. 41,924 करोड़ (12.9%) की ही वृद्धि दर्ज की गयी। खाद्यान्नेतर ऋण (पिछले वर्ष के रु. 40,789 करोड़ अथवा 15.1% की तुलना में रु. 37,594 करोड़ अथवा 12.1% रहा) में कमी मुख्यतः इस गिरावट का कारण रही। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण लिखतों (वाणिज्यिक पत्र सहित) तथा शेयर्स में निवेश सहित पिछले वर्ष के रु. 53,411 करोड़ की तुलना में रु. 54,143 करोड़ की निधियां उपलब्ध कराई गयी। वाणिज्यिक क्षेत्र को, पूंजी निर्गम, जीडीआर तथा वित्तीय संस्थाओं से उधार

incurred by the banking system have increased considerably. The RBI, therefore, made it mandatory for banks to put in place a system of Assets & Liabilities Management with effect from April 1, 1999.

During 1998-99 the RBI adopted policy measures aimed at stabilising the FOREX market, boosting industrial production, facilitating government borrowing programme, ensuring low inflation and easing interest rates. It endeavoured to achieve this via effective use of Open Market Operations, Repo transactions, CRR variation, Private Placement of Government Loans and changes in Bank Rate. The focus of these short term measures was on regulating liquidity of the banking system according to emergent needs rather than being bound by the traditional practice of monitoring and controlling the growth rate of Money Supply within a specified band.

The new policy approach also appears to be supported by the recommendations of the Working Group on "Money Supply: Analytics and Methodology of Compilation" and their implementation. The Working Group had emphasised on liquidity measures apart from money supply.

The RBI did not attempt to stifle money supply ( $M_3$ ) growth despite its overstepping the targeted band of 15.0-15.5 per cent taking into account the sluggish industrial activity. Similarly, it avoided restrictive measures when inflation shot up mid-year, recognising that the flare-up was owing to a few commodities due to transitory supply bottlenecks.

The easy liquidity conditions, by and large, dissuaded RBI from reducing CRR (as per its medium-term policy goal) during the year. Starting the year with a CRR of 10 per cent, it was raised to 11 per cent in August '98 to stabilise volatility in the FOREX market. It was reduced to 10.5 per cent in March '99 to ease the liquidity with an objective to bring down interest rates.

Inflation rate, measured by the wholesale prices, on a point-to-point basis, was 5 per cent as of March 1999 compared to 5.3 per cent a year earlier, which eased the price situation further.

## ◀ Banking Trend ▶

The year 1998-99 was marked by a general downtrend in nominal interest rates. With the easing of liquidity, major banks tended to cut interest rates on credit even prior to effecting corresponding changes in deposit rates.

This, perhaps, reflected their concern at the lack of pick-up in demand for credit for the second successive year. With most advances rates linked to PLR a downward adjustment tends to impact income generation almost across the scale. On the other hand, deposit rate cuts affect only fresh accruals and renewals. In the process the spreads took a beating more so as deposits continued with their buoyancy in 1998-99.

Aggregate deposits of the banking system registered a growth of 18.5 per cent as against 19.7 per cent in

the preceding year, attaining a level of Rs.7,17,271 crore compared to Rs. 6,05,410 crore earlier.

A peculiarity of the deposit growth was the sharp rise in time deposits alongside a decline in demand deposits. Of the total rise in aggregate deposits of Rs.1, 11,861 crore during the year the time deposit component was Rs.1,00,894 crore. Consequently the share of time deposits rose to 84.2 per cent from 83.1 per cent. Even if the impact of Resurgent India Bonds is discounted, the time deposit component rose to 83.7 per cent.

The rise in time deposits can partly be explained by the new maturity band of 15-29 days. Another contributory factor has probably been the rise in disposable income of the service sector.

Net Bank credit of the banking system recorded a lower increase of Rs.41,924 crore (12.9%) compared to Rs.45,678 crore (16.4%) in the previous year. The lower order of increase in non-food credit (Rs.37,594 crore or 12.1 % against Rs. 40,789 crore or 15.1% last year) mainly accounted for this fall. Total inflow of funds from Scheduled Commercial Banks to the Commercial Sector including banks' investment in debt instruments (including commercial paper) and shares amounted to Rs.54,143 crore against Rs.53,411 crore in the preceding year. Total resource flow to commercial sector including Capital issues, GDRs and borrowings from financial institutions was lower at Rs.1,04,474 crore relative to Rs.1,06,134 crore in the earlier year.